पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अभिसूचना

नई दिल्ली, 22 जून, 2015

का.आ. 1657(अ)–लिखित प्रारूप अधिसूचना, जिसे केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) तथा उपधारा (3) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जारी करने का प्रस्ताव करती है, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) की अपेक्षानुसार, जनसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित की जाती है: जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है, और यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप अधिसूचना पर, उस तारीख से, जिसको इस अधिसूचना वाले भारत के राजपत्र की प्रतियों जनसाधारण को उपलब्ध कराए दी जाती हैं, साथ दिन अवधि की समाप्ति पर या उसके पश्चात विचार किया जाएगा; जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, जो बाग रोड, अलीगंज, नई दिल्ली-110003 या ई-मेल पते: esz-mef@nic.in पर संबंधित रूप में झेल सकेगा।
प्रारूप अधिसूचना

और, बीर गुरुदारालपुरा वन्यजीव अभायारण्य, 620.53 हैक्टेयर में कैला पठियाला जिले का एक प्रमुख संरक्षित क्षेत्र है और यह पठियाला शहर से 45 कि.मी. की दूरी पर स्थित है और उक्त विनिर्देश इस संरक्षित क्षेत्र की अच्छी पारिस्थितिक उपयोगिता है और इसका एक सामान्य यह है कि घनघर नदी इसमें से गुजरती है ;

और, चैत्रविंशती और ठग के वन्य वर्गायुक्त के अनुसार वन जो, सम्पूर 5 (ख) - उत्तरी शुष्क निषिद्ध पर्याय वन प्रकार के अधीन आते हैं और जिसमें शीशाम, कीकर, ढाल, बेरी, जंगल, सिंभल, जागुन, नीम, तूफ, अज्जुन, कारी, काया, नारा, अन्न, खजुर, कारांश, बेन्जू आदि वृक्ष की प्रमुख प्रजातियां हैं, मुख्य रूप से गन्ध संके दो वृक्ष की अधिकता हो रही है ;

और, यह क्षेत्र विविध प्रकार के जानवरों और पक्षियों के अभिनव प्रोक्षण के लिए जाना जाता है और साही मछली, जंगली सुअर, बंदू बुल, शियाय, जंगली विल्ली, लघुपुच्छ बंदर, पी फाइल, काले और सलेटी तीतर, ढेरहरा तोता और फाकुता आदि प्रमुख जीव जन्तु प्रजातियां हैं ;

और, उक्त, बीर गुरुदारालपुरा वन्यजीव अभायारण्य संरक्षित क्षेत्र के घाटों और के क्षेत्र को जिसका विस्तार और सीमाएँ इस अधिसूचना के पैरा 1 में विनिर्देश है को, पारिस्थितिकीय और पर्यावरणीय दृष्टि से पारिस्थितिकीय संवेदी जोन के रूप में संरक्षित और सुरक्षित करना आवश्यक है जिससे उक्त पारिस्थितिक संवेदी जोन में उद्योगों या उद्योगों के वर्गों के प्रचालन और प्रसंस्करण को प्रतिष्ठित किया जा सके ।

अतः, अब, केंद्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) और पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiii) के साथ पठित और उपधारा (1) दुरारा प्रदत्त शब्दियों का प्रयोग करते हुए. पंजाब राज्य में बीर गुरुदारालपुरा वन्यजीव अभायारण्य की सीमा से 100 मीटर तक के विस्तारित क्षेत्र को बीर गुरुदारालपुरा वन्यजीव अभायारण्य पारिस्थितिक संवेदी जोन (जिसके इसमें इसके पशुपालन पारिस्थितिक संवेदी जोन कहा गया है) के रूप में अधिसूचित करती है, जिसकी पर्यावरण निगमनादृष्टि है, अर्थात् :--

1. पारिस्थितिक संवेदी जोन का विस्तार और उसकी सीमाएँ—(1) पारिस्थितिक संवेदी जोन 110.73 हैक्टेयर के क्षेत्र में समाविष्ट बीर गुरुदारालपुरा वन्यजीव अभायारण्य की सीमा से 100 मीटर तक विस्तारित होगा।

(2) पारिस्थितिक संवेदी जोन पूर्व-दक्षिण (उपाध्याय । मानचित्र के बिन्दु सं. ख) की ओर 76°13'43.194"उत्तर अंकाश और 30°3'9.04"पूर्व देशान्तर ; पश्चिम (उपाध्याय । मानचित्र के बिन्दु सं. य) की ओर 30°2' 33.556"उत्तर अंकाश तथा 76° 11'31.694" पूर्व देशान्तर; उत्तर (उपाध्याय । मानचित्र के बिन्दु सं. क) की ओर 30° 3'47.603"उत्तर अंकाश और 76° 13'11.919" पूर्व देशान्तर और दक्षिण (उपाध्याय । मानचित्र के बिन्दु सं. घ) की ओर 30° 2' 1.249"उत्तर अंकाश तथा 75° 52' 32.473" पूर्व देशान्तर से धिरा हुआ है।
(3) पारिस्थितिक संवेदी जोन की सीमा का मानचित्र इस अधिसूचना से उपाय अंशांश और देशांतर के साथ उपायांश I के रूप में दिया गया है।

(4) वन-जीव अभयारण्य पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर आने वाले 5 गांवों की सूची उनके अंशांश और देशांतर सहित प्रमुख बिन्दुओं के साथ उपायांश II के रूप में उपाय बना है।

2. पारिस्थितिक संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना—(1) राज्य सरकार, पारिस्थितिक संवेदी जोन के प्रयोजन के लिए राज्यपत्र में इस अधिसूचना के अंतिम प्रकाशण की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर, स्थानीय व्यक्तियों के परामर्श से, इस अधिसूचना में संलग्न अनुबंधों के सामर्थ्य से आंचलिक महायोजना तैयार करेगी।

(2) आंचलिक महायोजना राज्य सरकार में सभी प्रशिक्षार्थी द्वारा अनुमोदित होगी।

(3) पारिस्थितिक संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट रूप में ऐसी रीति में राज्य सरकार तथा सुसंगठन केंद्रीय और राज्य विभिन्न के सामर्थ्य में भी तथा केंद्रीय सरकार द्वारा जारी मार्गदर्श, यदि कोई हो, दूसरा तैयार होगी।

(4) आंचलिक महायोजना, पर्यावरणीय और पारिस्थितिकीय विचारों को समाकलित करने के लिए निम्नलिखित सभी संबंध राज्य सरकार के विभागों के परामर्श से तैयार होगी, अर्थात्—

(i) पर्यावरण;
(ii) वन;
(iii) नगर विकास;
(iv) पर्यटन;
(v) नगरपालिका;
(vi) राजस्थान;
(vii) कृषि; और
(viii) पंजाब राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,

(5) आंचलिक महायोजना अनुमोदित विद्यमान भू-उपयोग, अवसर-निर्माता और क्रियाकलापों पर कोई निबंधन अधिरोपित नहीं करेगी जब तक कि इस अधिसूचना में और आंचलिक महायोजना में सभी अवसर-निर्माता और अधिक प्रभावी और पारिस्थितिकीय अनुकूल क्रियाकलाप कारक इस प्रकार विनिर्दिष्ट न हो।

(6) आंचलिक महायोजना में अनावश्यक शर्तों के जीर्णोद्धार, विद्यमान जल निकायों के संक्रमण, आवाह क्षेत्रों के प्रबंधन, जल-संसाधन के प्रबंधन, भूतात्त्विक जल के प्रबंधन, मूडा और नमी संरक्षण, स्थानीय समुदायों की आवश्यकताओं तथा पारिस्थितिकीय और पर्यावरण से संबंधित ऐसे अन्य पहलुओं, जिन पर ध्यान देना आवश्यक है, के लिए उपाय बना होंगे।
(7) आंध्रप्रदेश राज्य सभा विधान मण्डल पूरा स्थल, याम और नगरीय वंदोबस्तों, वनों के प्रकार और खिस्मा, कृषि क्षेत्रों, उपजाऊ भूमि, हरित क्षेत्र जैसे उद्यान और उसी प्रकार के स्थान, उद्यान कृषि क्षेत्र, बगावत, जीलों और अन्य जल निकायों का अनुप्रयोग करें।

(8) आंध्रप्रदेश राज्य सभा पारिस्थितिक संवेदना जोन में विकास को पारिस्थितिक अनुकूल विकास और स्थानीय समुदायों की जीवनरूपांतरण को सुनिश्चित करते हुए विनियमित होगी।

3. राज्य सरकार द्वारा किए जाने वाले उपयोग-राज्य सरकार इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए निम्नलिखित उपाय करेगी, अर्थात् अवरोध के निम्नलिखित उपाय करेगी:

(1) भू-उपयोग-पारिस्थितिक संवेदना जोन में आमद-प्रमाण के प्रयोजन के लिए चिन्हित किए गए हैं वनों, उद्यान-कृषि क्षेत्रों, कृषि क्षेत्रों, पक्षी और खुले स्थानों का वाणिज्यिक और औद्योगिक संबंध विकास क्रियाकलापों के लिए उपयोग या संपरिवर्तन नहीं होगा:

परंतु पारिस्थितिक संवेदना जोन के भीतर कृषि भूमि का संपरिवर्तन माननीय समिति की सिफारिश पर और राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से, स्थानीय निवासियों की आवाजाही जस्तों को पूरा करने के लिए और पूर्व 4 की सारणी के स्तर (2) के अधीन नं 24, सं. 28, सं. 30, और सं. 35 के सामने सूचीबद्ध क्रियाकलापों को पूरा करने के लिए अनुमोदन होगा, अर्थात् अवरोध के निम्नलिखित उपाय करेगी:

(i) प्रबुद्ध उत्पन्न न करने वाले तथा उद्योग;
(ii) पारिस्थितिकीय अनुकूल पर्यटन क्रियाकलापों के लिए पर्यटकों के अस्थायी आवास के लिए पारिस्थितिकीय अनुकूल आरामगाह जैसे टेंट, लकड़ी के मकान आदि;
(iii) वर्षा जल संचय; और
(iv) कृषि उद्योग, जिसके अंतर्गत श्रमिक उद्योग भी हैं:

परंतु यह और भी कि राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन और संविधान के अनुच्छेद 244 या तत्समय प्रदूषण विधि के उपबंधों के अनुपालन के बिना, जिसके अंतर्गत अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत बन निवासी (बन अधिकारियों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) भी है, वाणिज्यिक या उद्योग विकास क्रियाकलापों के लिए जनजातीय भूमि का उपयोग अनुमोदन नहीं होगा:

परंतु यह और भी कि पारिस्थितिक संवेदना जोन के भीतर भू-अभिलेखों में उपसंजात कोई बुटी माननीय समिति के विचार प्राप्त करने के पश्चात् राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में एक बार संशोधित होगी और उक्त बुटी के संशोधन के केन्द्र सरकार के पर्यावरण, बन और जलवायु परिवर्तन मंचनल को सूचित देनी होगी।

परंतु यह और भी कि उपयुक्त बुटी के संशोधन में इस उप पैरा के अधीन यथा उपबंधन के सिवाय किसी भी दशा में भू-उपयोग का संसाधन समिलित नहीं होगा।

परंतु यह और भी कि जिससे हरित क्षेत्र में जैसे पौधा तथा कृषि जैसे अज्ञात में कोई परामर्शजनक करारों नहीं होगी और अनुपयुक्त या अनुपल्लवक कृषि क्षेत्रों में पूना वनीकरण करने के प्रयास किए जाएंगे।
(2) प्राकृतिक जल स्त्रील-आंचलिक महायोजना में सभी प्राकृतिक खोंचों की पहचान की जाएगी और उनके संरक्षण और पुनर्जीवनकरण के लिए योजना सभ्यीकृत होगी और राज्य सरकार द्वारा ऐसे क्षेत्रों पर या उनके निकट विकास क्रियाकलाप प्रतिष्ठित करने के लिए ऐसी रीति से मार्गदर्शक तैयार किए जाएंगे ।

(3) पर्यटन-(क) पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप, जो आंचलिक महायोजना का भाग रूप में सभ्यीकृत रूप में होंगे ।

(ख) पर्यटन महायोजना पर्यटन विभाग, पंजाब सरकार द्वारा राजस्व और वन विभाग, पंजाब सरकार के परमार्श से तैयार होगी ।

(ग) पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप सभ्यीकृत के अधीन विनियमित होंगे, अर्थात् :-

(i) पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर सभी नए पर्यटन क्रियाकलापों या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विवरण भारत सरकार के पर्यटक, वन और जलवायु परिवर्तन संसार के मार्गदर्शक सिद्धांतों के तहत वैदिक पर्यटन स्तरीय व्यवस्था संरक्षण प्राधिकरण, दुरारा जारी (समय-समय पर वातावरण) मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार, पारिस्थितिक पर्यटन, पारिस्थितिक शिक्षा और पारिस्थितिक विकास को महत्व देते हुए पारिस्थितिक संवेदी जोन की बहन श्रमक अध्ययन पर आधारित होगा ।

(ii) पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर होटल और रिसार्ट के नए संरचनाओं अनुमोदन नहीं होंगे ।

(iii) आंचलिक महायोजना का अनुमोदन किए जाने तक, पर्यटन के लिए विकास और विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों के विवरण को वास्तविक स्थिति विनिर्देशक संस्था तथा मानीदी सभ्यता की सिकारिता पर आधारित संरचना विनियमक प्राधिकारियों द्वारा अनुमोदित किया जाएगा ।

(4) नैसर्गिक विरासत-पारिस्थितिक संवेदी जोन में महत्वपूर्ण नैसर्गिक विरासत के सभी स्थलों जैसे सभी जीव की आर्थिक क्षेत्र, शैल विचरण, जल प्रपात, झरनाएं, घाटी मार्ग, उपवन, गुफाएं, स्थलों, श्रमण, अवशेषण, प्राणी आदि की पहचान की जाएगी और उन्हें सभ्यीकृत किया जाएगा तथा उनकी सूचना और संरक्षण के लिए इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से छह माह के भीतर, उपयुक्त योजना बनाएगी और ऐसी योजना जोनल मास्टर प्लान का भाग होगा ।

(5) मानव निर्मित विरासत स्थलों-पारिस्थितिक संवेदी जोन में भवनों, संरचनाओं, शिल्प-भवन, एतिहासिक, कलात्मक और सांस्कृतिक महत्व के क्षेत्रों की पहचान करनी होगी और इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से छह माह के भीतर उनके संरक्षण की योजनाएं तैयार करनी होगी तथा आंचलिक महायोजना में सभ्यीकृत की जाएगी ।

(6) ध्वनि प्रदूषण-पारिस्थितिक संवेदी जोन में ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण के लिए राज्य सरकार का परामर्श विभाग, वायु (प्रदूषण नियन्त्रण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) और
उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसरण में मार्गदर्शक सिद्धांत और विनियम तैयार करेगा।

(7) वायु प्रदुषण-परास्थितिक संबंधी जोन में, वायु प्रदुषण के नियंत्रण के लिए राज्य सरकार का पर्यावरण विभाग, वायु (प्रदुषण नियारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसरण में मार्गदर्शक सिद्धांत और विनियम तैयार करेगा।

(8) विद्यालय का निस्सारण-परास्थितिक संबंधी जोन में उपयुक्त विद्यालय का निस्सारण जल (प्रदुषण नियारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (1974 का 6) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार होगा।

(9) तोस अपशिष्ट-तोस अपशिष्टों का निपटान निम्नलिखित रूप में होगा -

(i) परास्थितिक संबंधी जोन में होस अपशिष्टों का निपटान भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं. का.आ. 908(अ), तारीख 25 सितंबर, 2000 नगरपालिका तोस अपशिष्ट (प्रबंध और हियालन) नियम, 2000 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा;

(ii) स्थानीय प्राधिकरण जैव निम्नीकरणीय और अर्जैव निम्नीकरणीय संघटनों में तोस अपशिष्टों के संपूर्णकरण के लिए योजनाएं तैयार करेंगे;

(iii) जैव निम्नीकरणीय सामग्री को अधिमानत: बाद बनाकर या कृमि खेती के माध्यम से पुनःचिकित्रित किया जाएगा;

(iv) अकार्बनिक सामग्री का निपटान परास्थितिक संबंधी जोन के बाहर पहचान किए गए स्थल पर किसी पर्यावरणीय स्वीकृत रीति में होगा और परास्थितिक संबंधी जोन में तोस अपशिष्टों का जलाना या क्षेत्रीय अनुसार नहीं होगा।

(10) जैव चिकित्सीय अपशिष्ट-परास्थितिक संबंधी जोन में जैव चिकित्सीय अपशिष्टों का निपटान भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की समय-समय पर यथासंशोधित अधिसूचना सं. का.आ. 630(अ) तारीख 20 जुलाई, 1998 द्वारा प्रकाशित जैव चिकित्सीय अपशिष्ट (प्रबंध और हियालन) नियम, 1998 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(11) यानीय परिवहन-परिवहन की यानीय गतिविधियाँ आवास के अनुमूल विनियम में होंगी और इस संबंध में आयोजक महायोजना में विशेष उपबंध अधिकृत किये जाएंगे और आयोजक महायोजना के तैयार होने और राज्य सरकार में सभी प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित होने तक, मानीयी समिति संबंधित अधिनियम और उसके अधीन बनाये गए नियम और विनियमों के अनुसार यानीय गतिविधियाँ के अनुमान को मानीया करेंगी।

4. परास्थितिक संबंधी जोन में प्रतिष्ठान और विनियमित क्रियाकलापों की सूची-परास्थितिक संबंधी जोन में सभी क्रियाकलाप पर्यावरण (संसर्ग) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) के उपबंधों और
उसके अर्थक बनाए गये नियमों द्वारा भारतीय होंगे और नवे दी गई तालिका में विनिर्दिष्ट रीति में विनियमित होंगे, अर्थात्—

<table>
<thead>
<tr>
<th>क्रम सं.</th>
<th>क्रियाकलाप कोड</th>
<th>टीका-टिप्पणी</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>वाणिज्यिक खजन, पत्रकार की खजन और उनके तोड़ने की इकाइयाँ।</td>
<td>(क) सभी प्रकार के नये और विद्युमान खजन (नयू और बुजुर्ग खमजा), पत्रकार की खजन और उनके तोड़ने की इकाइयाँ वाणिज्यिक स्थानिक विनियमों की घनी आवश्यकताओं के लिए भारतीय होंगे। (ख) खजन विनियम, माननीय अवधिकार न्यायालय की दो में विचार (विचार) सं. 1995 का 202 टीमा गोवा उपवर्तिक बनाए भारत सरकार के नये में आदेश तारीख 4.8.2006 और रिटर्न वाचिका (सी) सं. 2012 का 435 गोवा फाउंडेशन बनाए भारत सरकार के मामलों में तारीख 21.04.2014 के अंतर्गत आदेश के अनुसार में सर्व प्रायोजन होगा।</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>आरा मरीनों की स्थापना।</td>
<td>पारिस्थितिक संपत्ति जोन के भीतर नई और विद्युमान आरा मरीनों का विस्तार अनुमति नहीं होगा।</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>जन या वाहू या मृदा या ध्वनि प्रदूषण कारिगर करने वाले उद्योगों की स्थापना।</td>
<td>पारिस्थितिक संपत्ति जोन के भीतर नए और विद्युमान प्रदूषण कारिगर करने वाले उद्योगों का विस्तार अनुमति नहीं होगा।</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>किसी परिसंचालन पदार्थ का उपयोग या उत्पादन।</td>
<td>गांव विनियमों के अनुसार प्रतिष्ठित (अन्यथा उपभोगिता के लिए निवारण)।</td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>होटल और रिसेट का वाणिज्यिक स्थापना।</td>
<td>नए और विद्युमान वाणिज्यिक स्थापना है। रिसेट का पारिस्थितिक संपत्ति जोन के भीतर अनुमति नहीं होगा।</td>
</tr>
<tr>
<td>6</td>
<td>उत्तराखंड लक्ष्य का वाणिज्यिक उपयोग।</td>
<td>गांव विनियमों के अनुसार प्रतिष्ठित (अन्यथा उपभोगिता के लिए निवारण)।</td>
</tr>
<tr>
<td>7</td>
<td>जन या वाहू या मृदा या ध्वनि प्रदूषण कारिगर करने वाले उद्योगों का स्थापना।</td>
<td>गांव विनियमों के अनुसार प्रतिष्ठित (अन्यथा उपभोगिता के लिए निवारण)।</td>
</tr>
<tr>
<td>8</td>
<td>वर्षों से संबंधित क्रियाकलाप जैसे नर्म वाहु, गुड़ मकड़ी, गुड़ दूध अथवा अभावान्य क्षेत्र के क्षेत्र से उड़ने जैसे क्रियाकलाप करना।</td>
<td>गांव विनियमों के अनुसार प्रतिष्ठित (अन्यथा उपभोगिता के लिए निवारण)।</td>
</tr>
<tr>
<td>9</td>
<td>उद्योग और रिसेट का वाणिज्यिक उपयोग।</td>
<td>गांव विनियमों के अनुसार प्रतिष्ठित (अन्यथा उपभोगिता के लिए निवारण)।</td>
</tr>
<tr>
<td>10</td>
<td>प्राकृतिक जन नियमों या संरक्षण क्षेत्र में अनुपालित बाल्क्षक और डेट अप्लांडों का निर्माण।</td>
<td>गांव विनियमों के अनुसार प्रतिष्ठित (अन्यथा उपभोगिता के लिए निवारण)।</td>
</tr>
<tr>
<td>11</td>
<td>समलिंग क्रियाकलाप।</td>
<td>स्थानिक विनियमों की घनी आवश्यकताओं, जिसके अंतर्गत पैरा 3 के उप पैरा (1) में सुचीबद्ध क्रियाकलाप भी हैं, के लिए पारिस्थितिक संपत्ति जोन के भीतर किसी प्रकार के नये समलिंग अनुमति नहीं होगी। प्रदूषण न कारिगर करने वाले सभी उद्योगों से संबंधित समलिंग क्रियाकलाप के नये में विनियमित किया जाएगा और इसे नियमों द्वारा रखा जाएगा।</td>
</tr>
<tr>
<td>12</td>
<td>कृषि क्रियाकलाप।</td>
<td>(क) राज्य सरकार में कानून पारिपालन की पूर्व अनुमति के बिना, सरकारी या राजनीतिक व्यक्त या गृही मूल या बांग्लादेश में किसी कृषि क्रियाकलाप को नहीं होगी। (ख) कृषि क्रियाकलाप संबंधित क्षेत्र में राज्य अनुसूचित के उक्त कृषि क्रियाकलाप के अर्थों व नियमों द्वारा निर्देशन लाभ होगी।</td>
</tr>
<tr>
<td>13</td>
<td>कृषि प्रणालियों में अद्यतन परिवर्तन।</td>
<td>गांव विनियमों के अर्थों विनियमित होंगे।</td>
</tr>
</tbody>
</table>
| (14) | वाणिज्यिक जल संसाधन जिसके अंतर्गत भू-जल संचालन भी है। | (क) भूमि के अधिभोगी के वाणिज्यिक कृषि और पर्यटन क्षेत्र के लिए सतही और भूमिगत जल का वित्तीयगत अनुसरण होगा।
| | | (ख) आदेशनकार, वाणिज्यिक उपयोग के लिए सतही और भूमिगत जल का वित्तीयगत अनुसरण के लिए संबंधित वित्तीय कार्यक्रम पूर्व वित्तीय अनुसरण अनुसूची अनुरूपित होंगी जिसके अंतर्गत प्रदर्शन में वह वित्तीय गतिविधियाँ करेगा, भी है।
| | | (ग) सतही या भूमिगत का विकास अनुसूची नहीं होगा।
| | | (घ) किसी भी स्थिति से जल के संदर्भ में उपयोग, जिसके अंतर्गत कृषि भी है, को रोकने के लिए सभी पुरातात्विक कार्यालयों से जारी किया जाएगा।
| (15) | विद्युत केबलों और दूरसंचार दाताओं का परिवर्तन। | भूमिगत केबलों की योजना देना।
| (16) | हाटों और लॉर्ड के विद्युतक्षेत्र परिसरों में बाड़ लगाना। | सामू. विद्युत के अधीन वित्तीय बनाए रखे।
| (17) | विद्युतमाल सड़कों को चौक करना और उसके स्थानीय सड़कों किल्ले है। | उचित पर्यावरण दिल्ली में तथा औद्योगिक उपयोग या लागू अनुसूची होगा।
| (18) | पशु पालन के लिए जल का संचालन। | भूमि के अधीन वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए वित्तीय बनाए रखे।
| (19) | विशेष पृष्ठभूमि को लाना। | सामू. विद्युत के अधीन वित्तीय बनाए रखे।
| (20) | पांडा और नदी हार्दिक का संचालन। | सामू. विद्युत के अधीन वित्तीय बनाए रखे।
| (21) | वाणिज्यिक लाइफस्टाइल और हाथियाँ। | सामू. विद्युत के अधीन वित्तीय बनाए रखे।
| (22) | वाणिज्यिक (जिसके अंतर्गत ग्रामीण भी हैं) और वाणिज्यिक प्रदूषण। | सामू. विद्युत के अधीन वित्तीय बनाए रखे।
| (23) | प्राकृतिक जल निकायों या सहस्रताओं के लिए जल का संचालन। | उपचारित पवित्र के पुनर्वित्त की प्रौद्योगिकी करना और अबल या अन्य आपूर्तिकर्ता के लिए विद्युतमाल का अनुसरण करना होगा।
| (24) | प्रदूषण उपयोग करने वालों के लिए सामू. विद्युत। | पारिस्थितिक संबद्धी जोन से खेत प्रदूषण, गैर परिसंचालित, गैर लागू और लागू उद्योग, कृषि प्रदूषण, कृषि या आधारित देशी वस्तु से औद्योगिक प्रदूषण की उम्मीद के उद्योग और जो पर्यावरण पर कोई विशेष प्रभाव नहीं डालते हैं।
| (25) | बन उपयोग के लिए सामू. विद्युत के अधीन वित्तीय बनाए रखे। | पारिस्थितिक प्रयोजन के लिए सामू. विद्युत के अधीन वित्तीय बनाए रखे।
| (26) | सूचना सेवाओं के लिए। | पारिस्थितिक प्रयोजन के लिए सामू. विद्युत के अधीन वित्तीय बनाए रखे।
| (27) | मान्य आधारित उद्योग। | पारिस्थितिक संबद्धी जोन की नींवों के भीतर नए कार्य के आधारित उद्योग की वित्तीय बनाए रखे।
| (28) | पारिस्थितिक बनाए रखे। | परिस्थितिक संबद्धी जोन की नींवों के भीतर नए कार्य के आधारित उद्योग की वित्तीय बनाए रखे।
| (29) | स्थानीय समाजों द्वारा चर्चा चल रही कृषि और बाणीगी पार्थिवता के साथ प्रदूषण, पत्थरभार कृषि, जल कृषि और मछली पालन। | सामू. विद्युत के अधीन वित्तीय बनाए रखे।
5. पारिस्थितिक संबंधी जोन मानीटी समिति- (1) केन्द्रीय सरकार, पारिस्थितिक संबंधी जोन के प्रभावी मानीटी के लिए एक मानीटी समिति का गठन करेगी जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी,
अर्थात् :-

(क) मुख्य वन संस्थापक (वन्यजीव), पंजाब सरकार - अध्यक्ष;
(ख) ग्रामीण विकास और पंचायत विभाग का प्रतिनिधि, पंजाब सरकार - सदस्य;
(ग) पर्यावरण, वन और जलवायु पर्यावरण मंत्रालय का प्रतिनिधि - सदस्य;
(घ) राज्य रेलवे कार्यालय, पंजाब राज्य रेलवे नियंत्रण बोर्ड - सदस्य;
(ङ) पर्यावरण के क्षेत्र में कार्य करने वाले ओर सरकारी संगठनों (जिसके अंतर्गत विद्यालय संस्थान भी है) का एक वर्ग की अवधि के लिए मंजिला राज्य सरकार द्वारा नामंदिरित एक प्रतिनिधि - सदस्य;
(च) पंजाब सरकार द्वारा राज्य के किसी प्रतिष्ठित संस्था या विश्वविद्यालय का नामंदिरित पारिस्थितिक और पर्यावरण क्षेत्र का एक वर्ग की अवधि के लिए विशेषज्ञ - सदस्य;
(छ) ग्रामीण विकास और आवास विभाग, पंजाब सरकार का प्रतिनिधि-सदस्य;
(ज) कृषि विभाग, पंजाब सरकार का प्रतिनिधि - सदस्य;
(झ) जिला कलक्टर, पटियाला का प्रतिनिधि - सदस्य;
(ट) प्रखंड वन अधिकारी (पीएच का प्रभारी) - सदस्य-सचिव।

निर्देश निबंधन

(2) मानीटी समिति इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुपालन का मानीटी करेगी।

(3) पारिस्थितिक संबंधी जोन में भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1533(अ) तारीख 14 सितंबर, 2006 की अनुसूचियों में के अधीन सम्मिलित क्रियाकलापों और इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन प्रतिष्ठित गतिविधियों के सिवाय आने वाले ऐसे क्रियाकलापों की दशा में वास्तविक विनिर्दिश स्थलीय दशाओं पर आधारित मानीटी समिति द्वारा संबूच्छ की जाएगी और उक्त अधिसूचना के उपबंधों के अधीन पूर्ण पर्यावरण निकासी के लिए केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को निर्दिश की जाएगी।

2753 G/15-3
(4) इस अधिसूचना के पैरा 4 के अंधीन यथा विनिर्दिष्ट प्रतिष्ठित क्रियाकलापों के सिवाय, भारत सरकार के पर्यावरण, और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1533(अ) तारीख 14 सितंबर, 2006 की अधिसूचना के अनुसार इसे क्रियाकलापों, जिन्हें सम्मिलित नहीं किया गया है, परंतु पारिस्थितिक संबंधी जीव में आते हैं, ऐसे क्रियाकलापों की वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशा के आधारित मानिटी समिति द्वारा संविधा की जाएगी और उसे संबंध विनियमक प्राप्ति करने का निर्देश किया जाएगा।

(5) मानिटी समिति का सदस्य-सचिव या संबंध मुद्य वन संरक्षक (वन्य जीव) ऐसे व्यक्ति के विस्तार, जो इस अधिसूचना के किसी उपबंध का उल्लंघन करता है, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 19 के अंधीन परिवाद फाइल करने के लिए सक्षम होगा।

(6) मानिटी समिति मुद्य से मुद्यार के आधार पर अपेक्षाओं पर निर्भर रहते हुए संबंध विभागों के प्रतिनिधियों वा विशेषज्ञ, औद्योगिक संगठनों या संबंध पणाधारियों के प्रतिनिधियों को अपने विचार-विमर्श में सहायता के लिए आमंत्रित कर सकेगी।

(7) मानिटी समिति प्रत्येक वर्ष की 31 मार्च तक की अपनी वार्षिक कार्यावली रिपोर्ट राज्य के मुद्य वन जीव तार्कन को उपबंध III में उपबंधित कुल विधान के अनुसार उक्त वर्ष के 30 जून तक प्रस्तुत करेगी।

(8) केंद्रीय सरकार का पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय मानिटी समिति को अपने कृत्यों के प्रभावी निर्भर के लिए समय-समय पर ऐसे निर्देश दे सकेगी, जो वह ठीक समझे।

6. इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभाव देने के लिए केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार अतिरिक्त उपाय, यदि कोई हों, विनिर्दिष्ट कर सकेंगे।

7. भारत के मानिटी उच्चतम संस्थालय या उच्च न्यायालय या राष्ट्रीय हरित प्राप्ति करने द्वारा एक उदाहरण दे सकेगी। यदि कोई हों, के अंधीन, इस अधिसूचना के उपबंध होंगे।

[फा. सं. 25/36/2014-ईसरजेड-आर्थ]  
उपाध्याय 1

बीर गुरदालपुरा, बन्नजीव अभयारण्य, पंजाब की परिस्थितिकीय संवेदी जोन की सीमा का इसके अधिकतम और विस्तार के अक्षांश और देशांतर सहित वाचित्रित
उपाध्य-III

परिस्थितिक संबंधी जोन मानिट्री समिति-की गई कारंवाई की रिपोर्ट का रूप विधान

1. बैठकों की संख्या और तारीख।

2. बैठकों का कार्यपूर्त : कृपया मुख्य उल्लेखनीय बिंदुओं का वर्णन करें। बैठक के कार्यपूर्त को एक पृथ्वी अनुच्छेद में उपबंध करें।

3. आंचलिक महायोजना की तैयारी की प्रास्थिति जिसके अंतर्गत पत्रन महायोजना।

4. भू-अभिलेख में सदस्य दर्जें के सुझाव के लिए व्याकरण किया गया मामलों का सारांश।

5. पर्यावरण प्रभाव निर्धारण ईआईए अधिसूचना, 2006 के अधीन आने वाली गतिविधियों की संविक्षण के मामलों का सारांश। व्याप्तकृत उपबंध के रूप में उपबंध किया जा सकता है।

6. पर्यावरण प्रभाव निर्धारण ईआईए अधिसूचना, 2006 के अधीन न आने वाली गतिविधियों की संविक्षण के मामलों का सारांश। व्याप्तकृत उपबंध के रूप में उपबंध किया जा सकता है।

7. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन दर्ज की गई शिकायतों का सारांश।

8. कोई अन्य महत्वपूर्ण विषय।

उपाध्य-II

बीर गुरदयालपुरा वन्यजीव अभयारण्य, पंजाब की प्रस्तावित परिस्थितिकीय संबंधी जोन के भीतर आने वाले ग्रामों की सूची

<table>
<thead>
<tr>
<th>क्रम सं.</th>
<th>नाम संबंधी</th>
<th>अक्षांश</th>
<th>देशांतर</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>डिग्री</td>
<td>मिनट</td>
<td>सेकंड</td>
</tr>
<tr>
<td>1.</td>
<td>मरदानहरी</td>
<td>30</td>
<td>03</td>
</tr>
<tr>
<td>2.</td>
<td>दाबानखेरी</td>
<td>30</td>
<td>01</td>
</tr>
<tr>
<td>3.</td>
<td>हरचन्दपुरा</td>
<td>30</td>
<td>01</td>
</tr>
<tr>
<td>4.</td>
<td>मरोही</td>
<td>30</td>
<td>04</td>
</tr>
<tr>
<td>5.</td>
<td>पुष्पमाजस  (सीपोमाजश)</td>
<td>30</td>
<td>02</td>
</tr>
</tbody>
</table>
MINISTRY OF ENVIRONMENT, FORESTS AND CLIMATE CHANGE
NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd June, 2015

S.O. 1657(E).—The following draft of the notification, which the Central Government proposes to issue in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (v) and clause (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) is hereby published, as required under sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, for the information of the public likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft notification shall be taken into consideration on or after the expiry of a period of sixty days from the date on which copies of the Gazette of India containing this notification are made available to the public;

Any person interested in making any objections or suggestions on the proposals contained in the draft notification may forward the same in writing, for consideration of the Central Government within the period so specified to the Secretary, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Indira Paryavaran Bhawan, Jorbagh Road, Aliganj, New Delhi-110 003, or at e-mail address: esz-mef@nic.in

Draft Notification

Whereas, Bir Gurdialpura Wildlife Sanctuary having an area of 620.53 hectares is one of the important protected areas of the Patiala District and is situated 45 Kilometres from Patiala city and 15 Kilometres from Patiala-Samana Road.

And Whereas, the above specified this protected area has good ecological value and one of the strength is that river Gaggar passes through it.

And Whereas, the protected area, as per the forest classification of Champion and Seth, has the forests that fall under the sub-group 5(b) Northern Dry Mixed Deciduous Forest Type and the main tree species are Shisham, Kikkar, Dhak, Beri, Jand, Simbal, Jumun, Neem, Toot, Arjun, Karer, Kahi, Nara, Amb, Khajoor, Karonda, Bamboo, etc., being relatively dominated by Eucalyptus trees;

And Whereas, the area is known to support a variety of animals and birds and the main faunal species are Porcupine, Wild Boar, Blue Bull, Jackal, Jungle Cat, Rhesus Monkey, Peafowl, Black and Grey Partridges, Parakeets and Doves etc;

And Whereas, it is necessary to conserve and protect the area, the extent and boundaries of which are specified in paragraph 1 of this notification around the protected area of the Bir Gurdialpura Wildlife Sanctuary as Eco-sensitive Zone from ecological and environmental point of view and to prohibit industries or class of industries and their operations and processes in the Said Eco-Sensitive Zone;

Now Therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1), clause (v) and clause (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby notifies the area to an extent up to 100 metres all around the boundary of the Bir Gurdialpura Wildlife Sanctuary in the State of Punjab as an Eco-sensitive Zone (hereinafter referred to as the Eco-sensitive Zone), details of which are as under, namely:-

1. Extent and boundaries of Eco-sensitive Zone.— (1) The extent of Eco-sensitive Zone is an area to an extent of 100 meters all around the boundary of the Bir Gurdialpura Wildlife Sanctuary comprising an area of 110.73 hectares.

(2) The Eco-sensitive Zone is bounded by 30°3’9.04”N latitude and 76°13’43.194”E longitude towards East (Reference point No.B of Annexure I map); 30°2’33.556”N latitude and 76°11’31.694”E longitude towards west (Reference point No.E of Annexure I map); 30°3’47.603”N latitude and 76°13’11.919”E longitude towards north (Reference point No.A of Annexure I map) and 30°2’21.249”N latitude and 75°52’32.473”E longitude towards south (Reference point No.D of Annexure I map).

(3) The map showing the boundaries of the Eco-sensitive Zone together with its latitudes and longitudes is appended as Annexure I.

(4) A list of five villages falling within the Eco-sensitive Zone along with their longitudes and latitudes at prominent points are appended as Annexure II.

2. Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone.— (1) The State Government shall, for the purpose of the Eco-sensitive Zone prepare, a Zonal Master Plan, within a period of two years from the date of publication of final notification in the Official Gazette, in consultation with local people and adhering to the stipulations given in this notification.

27 53 65 | 15 4
(2) The Zonal Master Plan shall be approved by the Competent Authority in the State Government.

(3) The Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone shall be prepared by the State Government in such manner as is specified in this notification and also in consonance with the relevant Central and State laws and the guidelines issued by the Central Government, if any.

(4) The Zonal Master Plan shall be prepared in consultation with all concerned State Departments namely:-

(i) Environment;
(ii) Forest;
(iii) Urban Development;
(iv) Tourism;
(v) Municipal;
(vi) Revenue;
(vii) Agriculture; and
(ix) Punjab State Pollution Control Board.

(5) The Zonal Master Plan shall not impose any restriction on the approved existing land use, infrastructure and activities, unless so specified in this notification and the Zonal Master Plan shall factor in improvement of all infrastructure and activities to be more efficient and eco-friendly.

(6) The Zonal Master plan shall provide for restoration of denuded areas, conservation of existing water bodies, management of catchment areas, watershed management, groundwater management, soil and moisture conservation, needs of local community and such other aspects of the ecology and environment that need attention.

(7) The Zonal Master Plan shall demarcate all the existing worshipping places, village and urban settlements, types and kinds of forests, agricultural areas, fertile lands, green area, such as, parks and like places, horticultural areas, orchards, lakes and other water bodies.

(8) The Zonal Master Plan shall regulate development in Eco-sensitive Zone so as to ensure Eco-friendly development and livelihood security of local communities.

3. **Measures to be taken by State Government.**—The State Government shall take the following measures for giving effect to the provisions of this notification, namely:-

(1) **Land use.**—Forests, horticulture areas, agricultural areas, parks and open spaces earmarked for recreational purposes in the Eco-sensitive Zone shall not be used or converted into areas for commercial or industrial related development activities:

Provided that the conversion of agricultural lands within the Eco-sensitive Zone may be permitted on the recommendation of the Monitoring Committee, and with the prior approval of the State Government, to meet the residential needs of local residents, and for the activities listed against serial numbers 24, 28, 30 and 35 in column (2) of the Table in paragraph 4, namely:-

(i) Small scale industries not causing pollution;

(ii) Eco-friendly cottages for temporary occupation of tourists such as tents, wooden houses, etc. for Eco-friendly tourism activities;

(iii) Rainwater harvesting, and

(iv) Cottage industries including village artisans, etc:

Provided further that no use of tribal land shall be permitted for commercial and industrial development activities without the prior approval of the State Government and without compliance of the provisions of article 244 of Constitution or any other law for the time being in force, including the Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (2 of 2007):

Provided also that any error appearing in the land records within the Eco-sensitive Zone shall be corrected by the State Government, after obtaining the views of the Monitoring Committee, only once in each case and the correction of said error shall be intimated to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change:

Provided also that the above correction of error shall not include change of land use in any case except as provided under this sub-paragraph:
Provided also that there shall be no consequential reduction in green area, such as forest area and agricultural area and efforts shall be made to reforest the unused or unproductive agricultural areas.

(2) **Natural Springs.**—The catchment areas of all natural springs shall be identified and plans for their conservation and rejuvenation shall be incorporated in the Zonal Master Plan and guidelines shall be drawn up by the State Government in such a manner so as to prohibit development activities at or near these areas which are detrimental to such areas.

(3) **Tourism.**—(a) The activity relating to tourism within the Eco-sensitive Zone shall be as per Tourism Master Plan, which shall form part of the Zonal Master Plan.

(b) The Tourism Master Plan shall be prepared by the Department of Tourism, Government of Punjab in consultation with Department of Revenue and Forests, Government of Punjab.

(c) The activity of tourism shall be regulated as under, namely:-

(i) all new tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the eco-tourism guidelines issued by the National Tiger Conservation Authority, Ministry of Environment, Forests and Climate Change (as amended from time to time) with emphasis on eco-tourism, eco-education and eco-development and based on carrying capacity study of the Eco-sensitive Zone;

(ii) new construction of hotels and resorts shall not be allowed within the Eco-sensitive Zone;

(iii) till the Zonal Master Plan is approved, development for tourism and expansion of existing tourism activities shall be permitted by the concerned regulatory authorities based on the actual site specific scrutiny and recommendation of the Monitoring Committee.

(4) **Natural Heritage.**—All sites of valuable natural heritage in the Eco-sensitive Zone, such as the gene pool reserve areas, rock formations, waterfalls, springs, gorges, groves, caves, points, walks, rides, cliffs, etc., shall be identified and preserved and proper plan shall be drawn up for their protection and conservation, within six months from the date of publication of this notification and such plan shall form part of the Zonal Master Plan.

(5) **Man-made heritage sites.**—Buildings, structures, artefacts, areas and precincts of historical, architectural, aesthetic, and cultural significance shall be identified in the Eco-sensitive Zone and plans for their conservation shall be prepared within six months from the date of publication of this notification and incorporated in the Zonal Master Plan.

(6) **Noise pollution.**—The Environment Department of the State Government shall draw up guidelines and regulations for the control of noise pollution in the Eco-sensitive Zone in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981) and the rules made thereunder.

(7) **Air pollution.**—The Environment Department of the State Government shall draw up guidelines and regulations for the control of air pollution in the Eco-sensitive Zone in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981) and the rules made thereunder.

(8) **Discharge of effluents.**—The discharge of treated effluent in Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the provisions of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 (6 of 1974) and the rules made thereunder.

(9) **Solid wastes.**—Disposal of solid wastes shall be as under.—(i) the solid waste disposal in Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Municipal Solid Waste (Management and Handling) Rules, 2000 published by the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests vide notification number S.O. 908(E), dated the 25th September, 2000, as amended from time to time;

(ii) the local authorities shall draw up plans for the segregation of solid wastes into biodegradable and non-biodegradable components;

(iii) the biodegradable material shall be recycled preferably through composting or vermiculture;

(iv) the inorganic material shall be disposed of in an environmentally acceptable manner at site identified outside the Eco-sensitive Zone and no burning or incineration of solid wastes shall be permitted in the Eco-sensitive Zone.

(10) **Bio-medical waste.**—The bio-medical waste disposal in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Bio-Medical Waste (Management and Handling) Rules, 1998 published by the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests vide notification number S.O. 630(E), dated the 20th July, 1998 as amended from time to time.

(11) **Vehicular traffic.**—The vehicular movement of traffic shall be regulated in a habitat friendly manner and specific provisions in this regard shall be incorporated in the Zonal Master Plan and till such time as the Zonal Master Plan is prepared and approved by Competent Authority in the State Government. The Monitoring Committee shall monitor compliance of vehicular movement under the relevant Acts and rules and regulations made thereunder.
4. List of activities prohibited or to be regulated within the Eco-sensitive Zone.—All activities in the Eco-sensitive Zone shall be governed by the provisions of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and the rules made thereunder and shall be regulated in the manner specified in the Table below, namely:-

TABLE

<table>
<thead>
<tr>
<th>Sl. No.</th>
<th>Activity</th>
<th>Remarks</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>A.</td>
<td>Prohibited Activities:</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
| 1.     | Commercial Mining, stone quarrying and crushing units. | (a) All new and existing mining (minor and major minerals), stone quarrying and crushing units are prohibited except for the domestic needs of bonafide local residents.  
(b) The mining operations shall strictly be in accordance to the orders of the Hon’ble Supreme Court dated 4th August, 2006 in the matter of T.N.Godavarman Thirumulpad Vs. Union of India in W.P(C) No.202 of 1995 and dated 21st April, 2014 in the matter of Goa Foundation Vs. Union of India in W.P(C) No.435 of 2012. |
| 2.     | Setting up of saw mills.                      | No new and expansion of existing saw mills shall be permitted within the Eco-sensitive Zone.                                               |
| 3.     | Setting up of industries causing water or air or soil or noise pollution. | No new or expansion of existing polluting industries shall be permitted within the Eco-sensitive Zone.                                     |
| 4.     | Use or production of any hazardous substances | Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.                                                                         |
| 5.     | Commercial establishment of hotels and resorts. | No new or expansion of existing commercial establishments such as hotels and resorts shall be permitted within the Eco-sensitive Zone. |
| 6.     | Commercial use of firewood.                  | Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.                                                                         |
| 7.     | Establishment of new major hydroelectric projects. | Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.                                                                       |
| 8.     | Undertaking activities related to tourism like over-flying the sanctuary area by hot-air balloons, etc. | Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.                                                                       |
| 9.     | Uses of plastic carry bags.                  | Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.                                                                         |
| 10.    | Discharge of untreated effluents and solid waste in natural water bodies or land area. | Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.                                                                         |
| 11.    | Construction activities.                     | No new construction of any kind shall be allowed within the Eco-sensitive Zone, except for the domestic needs of local residents including the activities listed at item numbers 30 and 35. In the case of activities listed at item number 24, the construction activity shall be regulated and kept at the minimum. |
| B.     | Regulated Activities :                       |                                                                                                                                          |
| 12.    | Felling of trees.                            | (a) There shall be no felling of trees on the forest land or Government or revenue or private lands without prior permission of the competent authority in the State Government.  
(b) The felling of trees shall be regulated in accordance with the provisions of the concerned Central or State Act and the rules made thereunder. |
14. Commercial water resources including ground water harvesting.  
   (a) The extraction of surface water and ground water shall be allowed only for bona fide agricultural use and domestic consumption of the occupier of the land.  
   (b) The extraction of surface water and ground water for industrial or commercial use including the amount that can be extracted, shall require prior written permission from the concerned Regulatory Authority.  
   (c) No sale of surface water or ground water shall be permitted.  
   (d) Steps shall be taken to prevent contamination or pollution of water from any source including agriculture.

15. Erection of electrical cables and telecommunication towers.  
   Promote underground cabling.

16. Fencing of existing premises of hotels and lodges.  
   Regulated under applicable laws.

17. Widening and strengthening of existing roads and construction of new roads.  
   Shall be done with proper Environment Impact Assessment and mitigation measures, as applicable

18. Movement of vehicular traffic at night.  
   Regulated for commercial purpose under applicable laws.

   Regulated under applicable laws.

20. Protection of hill slopes and river banks.  
   Regulated under applicable laws.

   Regulated under applicable laws.

22. Air (including noise) and vehicular pollution.  
   Regulated under applicable laws.

23. Discharge of treated effluents in natural water bodies or land area.  
   Recycling of treated effluent shall be encouraged and for disposal of sludge or solid wastes, the existing regulations shall be followed.

24. Small scale industries not causing pollution.  
   Non-polluting, non-hazardous, small-scale and service industry, agriculture, floriculture, horticulture or agro-based industry producing products from indigenous goods from the Eco-sensitive Zone which do not cause any adverse impact on environment.

25. Collection of Forest produce or Non-Timber Forest Produce (NTFP).  
   Regulated for commercial purpose under applicable laws.

26. Security Forces Camp  
   Regulated for commercial purpose under applicable laws.

27. New wood based industry.  
   No establishment of new wood based industry shall be permitted within the limits of Eco-sensitive Zone. Provided that new wood based industry may be set up in the Eco-sensitive using 100 per cent imported wood stock.

28. Eco-friendly cottages for temporary occupation of tourists such as tents, wooden houses, etc., for Eco-Friendly tourism activities  
   Regulated for commercial purpose under applicable laws.

C. Permitted Activities:

29. Ongoing agriculture and horticulture practices by local communities along with dairies, dairy farming and fisheries.  
   Permitted under applicable laws.

30. Rain water harvesting.  
   Shall be actively promoted.

   Shall be actively promoted.

32. Adoption of green technology for all activities.  
   Shall be actively promoted.
33. Use of renewable energy sources. Permitted under applicable laws.

34. Vegetative fencing. Permitted under applicable laws.

35. Cottage industries including village artisans, etc. Shall be actively promoted.

5. **Monitoring Committee.**—(1) The Central Government hereby constitutes a Monitoring Committee, for effective monitoring of the Eco-sensitive Zone, which shall comprise of the following, namely:-

(a) The Chief Conservator of Forests (Wildlife), Government of Punjab—Chairman;
(b) Representative Department of Rural Development and Panchayat, Government of Punjab—Member;
(c) Regional Office, Punjab State Pollution Control Board—Member;
(d) One representative of Non-governmental Organisations working in the field of environment to be nominated by the Government of Punjab for a term of one year in each case—Member;
(e) One expert in the area of ecology and environment to be nominated by the Government of Punjab for a term of one year in each case—Member;
(f) Representative Department of Rural Development and Housing Department, Government of Punjab—Member;
(g) Representative of Agricultural, Government of Punjab—Member;
(h) Representative of District Collector of Patiala—Member;
(i) Divisional Forest Officer (In-charge of PA)—Member Secretary.

**Terms of Reference:**

(2) The Monitoring Committee shall monitor the compliance of the provisions of Gazette Notification.

(3) The activities that are covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533(E), dated 14th September, 2006, and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the Central Government in the Ministry of Environment, Forests and Climate Change for prior environmental clearances under the provisions of the said notification.

(4) The activities that are not covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and forests number S.O. 1533(E), dated 14th September, 2006 and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the concerned Regulatory Authorities.

(5) The Member Secretary of the Monitoring Committee or the concerned Chief Conservator of Forests (Wildlife) shall be competent to file complaints under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) against any person who contravenes the provisions of this notification.

(6) The Monitoring Committee may invite representatives or experts from concerned Departments, representatives from Industry Associations or concerned stakeholders to assist in its deliberations depending on the requirements on issue to issue basis.

(7) The Monitoring Committee shall submit the annual action taken report of its activities as on 31st March of every year by 30th June of that year to the Chief Wildlife Warden of the State per proforma given in **Annexure III**.

(8) The Central Government in the Ministry of Environment, Forests and Climate Change may give such directions, as it deems fit, to the Monitoring Committee for effective discharge of its functions.

6. The Central Government and State Government may specify additional measures, if any, for giving effect to provisions of the notification.

7. The provisions of this Notification are subject to the orders, if any, passed, or to be passed, by the Hon’ble Supreme Court of India or the High Courts or the National Green Tribunal (NGT).

[F. No. 25/36/2014-ESZ/RE]

Dr. G. V. SUBRAHMANYAM, Scientist ‘G’
Map showing boundaries of the Eco-sensitive Zone of Bir Gurdialpura Wildlife Sanctuary, Punjab together with its latitudes and longitude of extremes and extent.

DISTANCE OF ECO-SENSITIVE ZONE 100 METRES (WLS BIR GURDIALPURA) PATIALA

S.NO COORDINATES
A 76°13'11.919"E  30°3'47.603"N
B 76°13'43.194"E  30°3'9.04"N
C 76°13'20.227"E  30°2'8.492"N
D 76°12'9.851"E  30°2'1.249"N
E 76°11'31.694"E  30°2'33.556"N
F 76°12'26.157"E  30°3'14.488"N

Legend
- VILLAGE
- GURDIALPURA 100 METERS
- GURDIALPURA
- RIVER
List of villages falling within the proposed Eco-sensitive Zone Bir Gurdialpura Wildlife Sanctuary, Punjab.

<table>
<thead>
<tr>
<th>S.No.</th>
<th>Name</th>
<th>Latitude</th>
<th>Longitude</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>Degree</td>
<td>Minute</td>
</tr>
<tr>
<td>1.</td>
<td>Mardanheri</td>
<td>30</td>
<td>03</td>
</tr>
<tr>
<td>2.</td>
<td>Daban Kheri</td>
<td>30</td>
<td>01</td>
</tr>
<tr>
<td>3.</td>
<td>Harchandpura</td>
<td>30</td>
<td>01</td>
</tr>
<tr>
<td>4.</td>
<td>Marori</td>
<td>30</td>
<td>04</td>
</tr>
<tr>
<td>5.</td>
<td>Suhmajra (Seonmajra)</td>
<td>30</td>
<td>02</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Proforma of Action Taken Report: Eco-sensitive Zone Monitoring Committee.—

1. Number and date of Meetings
2. Minutes of the meetings: Mention main noteworthy points. Attached Minutes of the meeting on separate Annexure.
4. Summary of cases dealt for rectification of error apparent on face of land record.
   Details may be attached as Annexure
   Details may be attached as separate Annexure.
   Details may be attached as separate Annexure.
8. Any other matter of importance.